

मामा ने दिया तीस हजार भांजों को अभयदान

प्रकाश पाण्डेय, भोपाल

दिल की बीमारी लेकर पैदा होने वाले बच्चों को अब असमय जान नहीं गंवाना पड़ेगी। प्रदेश के तीस हजार ऐसे बच्चे हैं जो हृदय रोग से संबंधित पांच बीमारियों की गिरफ्त में हैं जिनके लिए पन्द्रह साल तक की आयु जिन्दगी पर भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ऐसी योजना बना रहा है कि दो साल के अंदर सभी बच्चों का आपरेशन कर उनकी जिन्दगी बचाई जा सके। पहले चरण में पांच हजार बच्चे चिन्हित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना के नाम से तैयार की जा रही इस योजना में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें यह माना जा रहा है कि प्रति हजार बच्चों

में एक बच्चा हृदय रोग से पीड़ित है। प्रदेश में एक से पन्द्रह हजार आयु वर्ग में दो करोड़ नब्बे लाख बच्चे हैं। इस मान से 30 हजार बच्चे हृदय रोगी हैं और यदि वे इस बीमारी का इलाज करवाते हैं तो हर अभिभावक पर लगभग चार लाख का खर्च आएगा। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इतना पैसा खर्च कर पाना एक सपने की तरह है और वे मजबूरी में अपने बच्चों को सिर्फ मीत के मुंह में जाता देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत दिल की जिन छह बीमारियों को चिन्हित किया गया है उनमें आट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी आफ फेलोट, पेटेंट डक्टस आट्रियोसिस, कोआर्कटेशन आफ ऑरटो एवं विथ वाल्यूलर डिजीज के नाम शामिल हैं ये सभी जानलेवा बीमारी हैं। सबसे पहले यह मामला उस समय सामने आया जब इंदौर में लगाए गए बच्चों के एक परीक्षण शिविर में आए तीन सौ बच्चों में 110 बच्चे हृदय रोग से पीड़ित पाए गए। इसके बाद तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते धार के कैम्प में 69, उच्चैन में 60, रतलाम में 10, खरगौन में 62 और होशंगाबाद में नौ बच्चों के अंदर हृदय संबंधी बीमारी का पता चला और इसका निदान सिर्फ आपरेशन ही सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर विभाग ने सभी

मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना के तहत हृदय रोगी बच्चों का होगा इलाज, पहले चरण में पांच हजार आपरेशन

प्रति बच्चा एक लाख सोलह हजार का पैकेज

स्वास्थ्य विभाग ने आधा दर्जन हृदय संबंधी बीमारियों के जो बच्चे चिन्हित किए हैं उनमें से प्रत्येक के आपरेशन का खर्च 1 लाख 16 हजार रूपए निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के आठ बड़े अस्पतालों से इस मामले में संपर्क कर उन्हें योजना से अवगत कर कर सहमति भी प्राप्त कर ली है। राजधानी में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और चिंगु अस्पताल को इसमें शामिल किया गया है। जबकि इंदौर के चार अस्पताल योजना में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रथम चरण में जिन पांच हजार बच्चों को उपचार दिया जाना है उनके आवंटन जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएमएचओ के प्रमाणपत्र पर स्वास्थ्य विभाग को दिए जाएंगे। जहां से उन्हें तत्काल स्वीकृत कर बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है जिसे प्रमुख सचिव को प्रेषित किया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में पांच हजार बच्चों के हृदय रोग का उपचार कराया जाएगा।

डॉ. अशोक वीरांग, संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य विभाग

बच्चों के आपरेशन की जिम्मेदारी स्वीकार की। पहले तो जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि वे आपरेशन की व्यवस्था करएं, लेकिन संभावित बीमार बच्चों की संख्या तीस हजार से अधिक को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाने लगी। संचालनालय लोक स्वास्थ्य विभाग में योजना संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो बाद में प्रमुख सचिव के माध्यम से मंत्रीमंडल के समक्ष जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी।